भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3268
20 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

ऑपरेशन ग्रीन्सः "कुल" नाशवान वस्तुओं तक विस्तार

3268. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री मयंककुमार नायकः
श्री अमर पाल मौर्यः
श्री मिथलेश कुमारः
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री नरहरी अमीनः
श्री उज्जवल देवराव निकमः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में मूल 'टॉप' (टमाटर, प्याज, आलू) फसलों के अतिरिक्त, ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) मूल्य अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाने और परिवहन एवं भंडारण राजसहायता जैसे अल्पकालिक हस्तक्षेपों को लागू करने में "बाजार खुफिया नेटवर्क" की प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत बिचौलियों को हटाने के लिए प्रसंस्करण केंद्रों से सीधे जोड़े गए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की संख्या कितनी है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): 'ऑपरेशन ग्रीन्स-दीर्घकालिक हस्तक्षेप' योजना के अंतर्गत, मंत्रालय प्रति परियोजना ₹15 करोड़ रुपए की अधिकतम पात्र अनुदान सहायता के साथ चिन्हित उत्पादन क्लस्टरों में 10 फलों की फसलों, 11 सब्जियों की फसलों और झींगा की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए सामान्य क्षेत्रों के परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत 15 एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जिनमें से 2 परियोजनाओं को महाराष्ट्र राज्य में मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत स्वीकृत एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(ख): कीमत अस्थिरता का अनुमान लगाने के लिए और परिवहन और भंडारण सब्सिडी जैसे अल्पकालिक हस्तक्षेप शुरू करने में "मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क" की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इसके अलावा, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अल्पकालिक हस्तक्षेप घटक जो खराब फसलों के परिवहन और भंडारण सब्सिडी से संबंधित थे, को वर्ष 2023-24 से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ग): एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के माध्यम से, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत 45 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रसंस्करण केंद्रों से जोड़ा गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 20.03.2026 को उत्तर के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन्स: कुल "नाशवान वस्तुओं तक विस्तार" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3268 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत अनुमोदित एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजना की संख्या	जारी	पूर्ण	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान-सहायता (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	5	3	2	275.22	79.31	38.95
असम	1	1	0	28.53	7.40	2.47
गुजरात	4	1	3	303.63	70.55	50.24
मध्य प्रदेश	1	0	1	36.70	15.00	10.00
महाराष्ट्र	2	0	2	67.30	25.17	21.89
तमिलनाडु	2	1	1	40.00	19.76	18.14
कुल	**15**	**6**	**9**	**751.38**	**217.19**	**141.69**